सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

16-31 जनवरी, 2024 वर्ष : 1 अंक : 20

निःशुल्क प्रति

विकास के मानक केंद्र शासित प्रदेश

जम्मू-कश्मीर : विकास की नई गाथा

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

केंद्र शासित प्रदेश: विकास के पावरहाउस में बदलने की कोशिश	12
वीर नायकों के नाम पर हुआ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम	17
दशकों पुरानी आकांक्षा हुई पूरी	20
चंडीगढ़ में बहती रहेगी विकास की बयार	22
अब क्षेत्रीय भाषाओं में सीएपीएफ की होगी परीक्षा	24
सीमा पर स्थित गांव है देश का प्रथम गांव	25
गेस्ट कॉलम	26

विशेष रिपोर्ट

05 विकास के मानक केंद्र शासित प्रदेश

15 विकास की नई गाथा

18 पारदर्शिता के साथ बेहतर व्यवस्था

संपादक की कलम से...

भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेश एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनका निर्माण उनके छोटे आकार, भूगोल, प्रशासनिक आवश्यकताओं, अद्वितीय संस्कृति और रणनीतिक महत्व सहित विभिन्न कारणों से किया गया था। उनमें से कुछ में चुनी हुई सरकारें होने और कुछ में नहीं होने के बावजूद, सभी केंद्र शासित प्रदेश प्रमुख निर्णयों के लिए सीधे केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह हैं।

देश के आठ केंद्र शासित प्रदेशों में से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के मानचित्र पर सबसे बाद में अस्तित्व में आए हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश आतंकवाद और विकासात्मक ठहराव से जूझने के बाद सरकारी प्रयासों से अब तेजी से विकास पथ पर हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं और समुदाय के नेतृत्व वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इन क्षेत्रों की दशा में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है।

कुछ केंद्र शासित प्रदेश भारत के वैश्विक दृष्टिकोण और इंडो-पैसिफिक रणनीति से भी महत्वपूर्ण हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन और दीव के साथ-साथ लक्षद्वीप भी इस श्रेणी में आते हैं। वे भारत की समुद्री सुरक्षा और पड़ोस नीति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

> नवीन पायलट परियोजनाओं और योजनाओं के लिए आदर्श आधार बनाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की भौगोलिक सघनता और सरल प्रशासनिक ढांचा। इनकी सफलताओं को व्यापक राष्ट्रीय रणनीतियों में भी दोहराया जा सकता है।

विजन 2047 के लिए केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 दिसंबर, 2022 को 'केंद्र शासित प्रदेशों पर सम्मेलन' को संबोधित करते हुए केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2047 के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आदर्श वाक्य 'लोकल फॉर वोकल' और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' से प्रेरणा लेनी चाहिए एवं पर्यटन, विकास और कल्याण का केंद्र बनने का प्रयास करना चाहिए।

इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों के संस्कृति, पर्यटन स्थल, और विकास के अवसरों को साझा करने में मदद करेगा। यह स्थानीय संगठनों और समुदायों को भी उनकी विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षण करने के लिए उत्साहित करेगा। इसके अलावा, ये प्रयास भारत को ग्लोबल स्तर पर अपनी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा और मान्यता प्राप्त करने में मदद करेंगे।

दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा था कि इसका उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों और सामुदायिक पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों को स्थिति में लाना है। इस प्रकार वे आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बनें। मौजूदा 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भौगोलिक सघनता और सरल प्रशासनिक ढांचे उन्हें नवीन पायलट परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आदर्श आधार बनाते हैं, जिनकी सफलताओं को व्यापक राष्ट्रीय रणनीतियों में दोहराया जा सकता है। विशेष रूप से मत्स्य पालन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहकारी विकास पर नए सिरे से जोर देने का उद्देश्य बाहरी संसाधनों पर निर्भरता को कम करना और केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक जीवंतता की ओर प्रेरित करना है।

'सजग भारत' का यह अंक केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहे बदलावों पर केंद्रित है। हमेशा की तरह, हम अपने प्रयास पर आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। कृपया अपनी प्रतिक्रिया sajag-bharat@bprd.nic.in पर साझा करें।

जय हिंद!
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

यह बीते 10 वर्षों के सतत प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत की बेटियां थल, जल और नभ से लेकर अंतरिक्ष तक अपना लोहा मनवा रही हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ सशस्त्र सीमा बल सीमावर्ती इलाकों के इतिहास को सहेजने का काम कर रही है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था हुई सुदृढ़ और पुनर्जीवित हुआ प्रजातंत्र।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

Impressed by the skills of local artisans & craftsmen at the state-level Yuva Utsav 2024. Their stalls exuded the alluring charm of indigenous creations, truly capturing the essence of #VocalForLocal India. Let's continue promoting & uplifting our local talents!

Shri Nisith Pramanik
MoS, Ministry of Home Affairs

देश के उत्थान में समर्पित नायकों का सम्मान, यही है नए भारत की पहचान।

श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद पर नकेल कस मोदी सरकार ने यहाँ शांति के एक नए युग की शुरूआत की।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

विकास के मानक केंद्र शासित प्रदेश

> **विकसित भारत के निर्माण में लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका होगी। भारत सरकार, लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो जी 20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

ब्यूरो

जनवरी, 2024 के पहले सप्ताह में लक्षद्वीप में समुद्र के किनारे बैठे हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीरें मीडिया के जरिए सामने आने के बाद से ही जनता को अहसास हुआ कि देश का एक छोटा सा द्वीप समूह विकास के रास्ते पर चल कर कैसे दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर ऊपर आ गया है। यह घटना केवल लक्षद्वीप की रणनीतिक व कूटनीतिक महत्ता स्थापित नहीं करती, बल्कि बीते एक दशक से देश में खासतौर पर केंद्र शासित प्रदेशों के विकास की गाथा बयान करती है। इन सभी प्रदेशों में सरकार ने अनेक सुधार किए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचागत, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारिता, परिवहन, बिजली, अनुसंधान और विकास आदि शामिल हैं। बीते दशक में केंद्र सरकार ने द्विपीय क्षेत्रों पर अधिक फोकस किया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, दमन एवं दीव, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय

केंद्र शासित प्रदेशों में विकास की प्रक्रिया लगातार जारी है और कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। इन प्रदेशों में सरकार के प्रयासों ने अनेक क्षेत्रों में सुधार किया है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारिता, परिवहन, बिजली, अनुसंधान और विकास, आदि शामिल हैं। बीते दशक में केंद्र सरकार ने द्विपीय क्षेत्रों पर अधिक फोकस किया है। चाहे वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो या लक्षद्वीप का क्षेत्र। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन के साथ ही विकास के नए मानक गढ़ रहा है।

राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन के साथ ही विकास के नए मानक गढ़ रहा है। पुडुचेरी देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसने सौ प्रतिशत जन धन कवरेज हासिल की है। अनुसूचित जाति के कल्याण से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें भी शत प्रतिशत आधार कवरेज हासिल की जा चुकी है।

भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल के रूप में पूरे देश के सामने रखना चाहती है। सरकार का प्रयास है कि संघ, राज्य, और क्षेत्रीय स्तरों पर सुशासन और विकास के मॉडल को बेहतर बनाया जाए, ताकि देश की आर्थिक समृद्धि में सुधार किया जा सके। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो उत्कृष्ट संचालन, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन प्रयासों के माध्यम से, भारत सरकार सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर हो रही है। बीते कई वर्षों से प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए काम कर रहा है। विभागीय स्तर पर इसके लिए लगातार काम जारी है। तयशुदा कार्य योजना को क्रियान्वित करने और उसकी समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें होती रही हैं।

इन बैठकों के माध्यम से देश के सभी आठ केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत और लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए निर्णय लिए जाते रहे हैं।

पुडुचेरी क्षेत्रफल के हिसाब से देश के उन छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में से है, जिसको पूरे देश को दिशा देने की ताकत है। एक लाइट हाउस की तरह पुडुचेरी चमकते हुए अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के राज्यों को रास्ता दिखा सकता है। कम कैश इकॉनोमी से जुड़े कार्यों के जरिए, टूरिज्म से जुड़े नए ईको सिस्टम की स्थापना करके, एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट तैयार करके, सौ फीसदी एलईडी बल्ब वाला केंद्र शासित प्रदेश बनके, नए-नए इनोवेटिव तरीके से पुडुचेरी डवलपमेंट की नई मिसाल बन सकता है। **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

हम केवल वर्ष 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में लिए गए निर्णयों की बात करें, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद से पारित हो गया है। इसका लाभ आने वाले समय में दिल्ली की जनता को मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 4400 कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण पर नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही नई दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए ₹4800 करोड़ के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना- 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' को मंजूरी दे दी है, जिससे सीमावर्ती गांवों का विकास हो रहा है।

खास बात यह भी रही कि वैश्विक मंच पर भी पूरी दुनिया ने केंद्र शासित प्रदेशों की पूर्व की स्थिति में सुधार और वहां विकास की बयार को महसूस किया है। जी20 की तीसरी पर्यटन कार्य बैठक 22 से 24 मई 2023 तक श्रीनगर में जब आयोजित हुई, तो आए मेहमान अपने साथ

नई परिपाटी हुई शुरू

2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही श्री नरेन्द्र मोदी ने संघवाद को नई दिशा दी। अतीत की परिपाटी से हटते हुए प्रधानमंत्री ने चौतरफा विकास हासिल करने के लिए सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया। लंबे समय तक हमने केंद्र और राज्यों के बीच बड़े भाई जैसा संबंध देखा, 'सभी के लिए एक ही सांचे' का इस्तेमाल वर्षों तक किया गया। राज्यों को और अधिक मजबूती और शक्ति देने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। एक महत्वपूर्ण विकासमूलक कदम के तहत केंद्र से राज्यों की ओर एकतरफा प्रवाह की नीति को बदल दिया गया और इसकी जगह राज्यों के साथ एक वास्तविक और सतत भागीदारी ने ले ली है।

मधुर यादें संजोकर विदा हुए। सरकार के प्रयास से इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, क्योंकि 1.88 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का दौरा किया है। दिसंबर 2023 तक दो करोड़ से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नौ पर्यटक मार्ग और 30 ट्रैकिंग मार्ग खोले गए हैं। जम्मू देश का एकमात्र शहर है, जहां एक ही शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स) हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवाओं में गैर-राजपत्रित रैंक में महिला उम्मीदवारों के लिय सीधी भर्ती में उपलब्ध रिक्तियों में 15 प्रतिशत की सीमा तक क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। अगस्त 2019 से जम्मू-कश्मीर में अस्थायी रूप से लागू अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इसकी तस्वीर बदल गई है।

गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 4 दिसंबर,2023 को लद्दाख के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय लद्दाख के विकास में तेजी लाने और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्र शासित प्रदेश के गठन के इस ऐतिहासिक कदम के कारण प्रशासन और विकास को लद्दाख के लोगों के करीब लाया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद को प्रदान की गई धनराशि में वृद्धि, चौतरफा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और मोबाइल नेटवर्क, सड़कें, नए हेलीपैड के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचों का विकास भी तीव्र गति से किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के समग्र और सतत विकास के लिए एलएबी, केडीए और लद्दाख के लोगों के साथ नियमित आधार पर काम करना जारी रखेगी। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस ने संदर्भों की शर्तों को संशोधित करने और नए सदस्यों को शामिल करने के लिए गृह मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया। एलएबी और केडीए सदस्यों ने लद्दाख निवासियों के अधिकारों की रक्षा, भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी, एलएएचडीसी को मजबूत करने, विभिन्न माध्यमों द्वारा निर्णय लेने में अधिक भागीदारी जैसे विभिन्न मुद्दे रखे।

29 दिसंबर, 2022 को एक सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने संघ राज्य क्षेत्रों को 2047 के लिए अपना विजन तैयार करने का भी निर्देश दिया था और कहा था कि हर संघ राज्य क्षेत्र को अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षित संघ राज्य क्षेत्र, फ्लैगशिप स्कीमों में परिपूर्णता, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता पर बल देते हुए सभी संघ राज्य क्षेत्रों से बेस्ट प्रेक्टिस के आदान-प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा लक्ष्य सुस्पष्ट करें और जीवन में देश सेवा

केंद्रीय गृह मंत्रालय की फ्लैगशिप योजनाएं

- सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत धन का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरण।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में शत- प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत एलपीजी कवरेज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
- संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ प्रकार के एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
- संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चरण में संतृप्ति प्राप्त की है।
- सभी संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के अपने निर्धारित लक्ष्यों से अधिक केंद्र स्थापित किए हैं।
- 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में फेयर प्राइस शॉपस ऑटोमेटेड है।

के लिए मिले इस मौके को पूरा करें। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाओं को विकसित किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन, विकास और कल्याण का केंद्र बनने की दिशा में प्रयास करते हुए वोकल फॉर लोकल और एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक आकार में छोटे हैं और इनका प्रशासनिक ढांचा अपेक्षाकृत सरल है, इसलिए पायलट कार्यक्रमों के साथ प्रयोग करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र आदर्श प्रोटोटाइप हैं। इन प्रयोगों का संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर परीक्षण किया जा सकता है और फिर देश के बड़े क्षेत्रों और राज्यों में दोहराया जा सकता है।

श्री अमित शाह का कहना था कि सभी भारतीयों को भारत को 'सर्वश्रेष्ठ भारत' में बदलने का संकल्प लेना चाहिए। यह वर्ष 2047 के लिए एक समग्र विजन है। जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा। सभी संघ राज्य क्षेत्रों को 2047 के लिए एक रोडमैप और अगले 5 वर्षों के लिए एक कार्य योजना और अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करनी चाहिए। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की भी नियमित रूप से और कड़ाई के साथ निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए।

सम्मेलन ने संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के बीच क्रॉस लर्निंग और ज्ञान साझा करने का एक अवसर प्रदान करने के साथ ही संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आकांक्षाओं, उपलब्धियों, स्थानीय प्राथमिकताओं और अनूठी चुनौतियों को स्वर देने के लिए एक मंच प्रदान किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखने के समारोह में भाग लिया और नेता जी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाया जायेगा।

वर्तमान केंद्र सरकार देश के हर कोने तक विकास की रोशनी पहुंचाने का काम कर रही है। हर योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसी मानसिकता से प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सागरमाला योजना के अंतर्गत पुदुचेरी पोर्ट डेवलपमेंट की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि कार्य पूरा होने के बाद यह उन मछुआरों को लाभ प्रदान करेगा, जो मछली पकड़ने के लिए इस बंदरगाह का उपयोग करते हुए समुद्र में जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चेन्नई से समुद्री कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे पुदुचेरी के उद्योगों की कार्गो गतिविधि में मदद मिलेगी और चेन्नई बंदरगाह पर उतारने में मदद मिलेगी। इससे तटीय शहरों में यात्रियों की आवाजाही संभव हो सकेगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पुदुचेरी में संसाधन हैं, सामर्थ्य है, इच्छाशक्ति भी है और यहां के लोगों में विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता है। उनका यह भी कहना था कि सागरमाला परियोजना के माध्यम से सरकार ने बंदरगाहों को मजबूत किया और बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास के एक युग में प्रवेश किया है।

साल 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में पुदुचेरी के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, तो उस समय कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एक विकसित और प्रगतिशील पुदुचेरी के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिलवासा, दादरा और नगर हवेली में ₹4850 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण और दमन में सरकारी स्कूलों, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, विभिन्न सड़कों के सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण, मछली बाजार और शॉपिंग सेंटर और जल आपूर्ति योजना आदि का विस्तार जैसी 96 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है। प्रधानमंत्री ने दीव और सिलवासा से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शहरी के लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ₹5500 करोड़ के आवंटन के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर बहुत काम किया गया है। पिछले 9 वर्षों में एक नई कार्यशैली विकसित हुई है और कार्य संस्कृति शुरू हुई है, जो केंद्र सरकार के 'सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' पर आधारित है। उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र का संतुलित विकास हो, इस पर हमारा बहुत जोर है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की, कि दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से परिपूर्ण होने के बहुत करीब हैं। उनका मानना है कि 'सबका प्रयास' के साथ विकसित भारत और समृद्धि का संकल्प हासिल किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कदम जैसे पर्यटन को बढ़ावा देना, दूरसंचार और वेब कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सड़क, समुद्र और हवाई कनेक्टिविटी का विकास, स्वच्छ और हरित ऊर्जा का विकास और प्रचार, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की पहल सहित अपशिष्ट प्रबंधन, नई बिजली परियोजनाओं को चालू करना,

बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना आदि उठाए हैं। द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने विश्व स्तरीय समुद्री मोर्चे और प्रमुख नदी मोर्चे विकसित किए हैं। द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेशों में ईको-पर्यटन रिसॉर्ट विकसित किए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खगोलीय-पर्यटन और स्थानीय समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हानले में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है।

लगभग ₹1,224 करोड़ की लागत से चेन्नई अंडमान निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना के चालू होने से द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड और मोबाइल/डिजिटल कनेक्टिविटी में काफी वृद्धि हुई है। इस परियोजना ने इंटरनेट कनेक्टिविटी में क्रांति पैदा कर दी है और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैंडविड्थ उपयोग को 4.1 गीगा बाइट प्रति सेकेंड (जीबीपीएस) से बढ़ाकर 70.31 जीबीपीएस कर दिया है, इंटरनेट की गति 100 किलो बाइट प्रति सेकेंड (केबीपीएस) से बढ़कर 300 मेगा बाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) हो गई है, कुल मोबाइल कनेक्शन 4.7 लाख से बढ़कर लगभग 7 लाख हो गए हैं और फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) सेवाएं, जो सीधे घर और कार्यालयों को उच्च ब्रॉडबैंड गति प्रदान करती हैं, बढ़कर लगभग 34,500 हो गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 5जी सेवाएं भी शुरू की गई हैं।

सरकार केंद्र शासित प्रदेशों में हवाई, सड़क और समुद्री कनेक्टिविटी पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नया टर्मिनल भवन लगभग ₹710.00 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 50 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की है। ₹203.00 करोड़ की लागत से हम्फ्री स्ट्रेट पर 'आजाद हिंद फौज सेतु' ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी में काफी सुधार किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में मत्स्य पालन और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विभिन्न पहल की हैं। समग्र विकास के लिए मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और रसद, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, जलीय कृषि, क्षमता निर्माण और मत्स्य पालन प्रबंधन के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज भी बना रही है और मत्स्य पालन से संबंधित सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा दे रही है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जैसी एजेंसियां मछुआरों और मछली किसानों को उनकी क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम पहल की शुरूआत ने अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और वित्तीय परिवर्तन लाया है जिसके परिणामस्वरूप केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवसायों और आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिला है और उन्हें आर्थिक समृद्धि (आत्मनिर्भर अर्थव्यस्था) और विकसित भारत के नए चालकों के रूप में भी बढ़ावा मिला है। ■

केंद्र शासित प्रदेश : विकास के

वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर

सरकार पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र शासित प्रदेशों को विकास और आर्थिक महाशक्तियों का मॉडल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करना है, जो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने और वर्ष 2047 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह, ने उस महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया है, जो केंद्र शासित प्रदेश देश की 'आत्मनिर्भर भारत' की यात्रा में निभाएंगे। सामूहिक प्रयास और तालमेल की आवश्यकता पर जोर देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय उद्देश्यों और दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को एक साझा मंच पर एकजुट होने का आह्वान किया है।

तालमेल के माध्यम से क्षमता का उपयोग

श्री अमित शाह ने पायलट कार्यक्रमों के लिए आदर्श प्रोटोटाइप के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों की अद्वितीय स्थिति पर प्रकाश डाला था। 29 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा

पावरहाउस में बदलने की कोशिश

कि छोटे भौगोलिक आकार और सरल प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेशों को बड़े राज्यों में दोहराने से पहले छोटे पैमाने पर नवीन पहलों का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त बनाती है। उन्हें एक साथ आना चाहिए और देश को विकास की यात्रा में आगे ले जाने के लिए सहक्रियात्मक रूप से काम करना चाहिए।

वर्ष 2047 के लिए दृष्टिकोण

भारत 2047 में आजादी के 100 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने सभी भारतीयों से देश को बदलने और इसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अगले पांच वर्षों की स्पष्ट कार्य योजना के साथ 2047 के लिए एक विस्तृत रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है।। इस योजना में अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और कठोर समीक्षा शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, श्री शाह ने अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और परिवहन लागत को कम करने के लिए देश के भीतर पर्यटक सर्किट के विकास की वकालत की। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी विरासत पर गर्व करने और अपनी अपार पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा विकास समाज के सबसे दूरस्थ और सबसे वंचित सदस्यों पर इसके सकारात्मक प्रभाव से मापा जाता है, न कि केवल बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी के अमृत काल के 'पंच प्रण' (पांच संकल्प) को दोहराया। केंद्र शासित प्रदेशों से इन सिद्धांतों को अपनाने का आग्रह करते हुए सुरक्षित केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण, प्रमुख योजनाओं में संतृप्ति प्राप्त करना, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, भ्रष्टाचार को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति एवं समग्र विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करने की बात कही।

श्री शाह के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा, भावी पीढ़ियों में इन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष रूप से पुडुचेरी को श्री अरबिंदो के प्रेरणादायक जीवन के बारे में दस्तावेजीकरण करने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो प्रशासन के लिए मूल्यवान सीख है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों से बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए अपने विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देने का आग्रह किया, ताकि राजस्व हानि कम हो।

सतत एवं समावेशी विकास की ओर

सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का बहुआयामी दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुआयामी दृष्टिकोण में पर्यटन को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल है। जैसा कि गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने 20 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक जवाब में कहा था कि ये पहल विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं।

पर्यटन, जिसे इसके गुणक प्रभाव के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, को पारिस्थितिक पर्यटन, विरासत पर्यटन, साहसिक पर्यटन और विशिष्ट पर्यटन गतिविधियों सहित विभिन्न रूपों के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया है, जबकि दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली ने विश्व स्तरीय समुद्र और नदी तट विकसित किए हैं। खगोल-पर्यटन को बढ़ावा देने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए लद्दाख के हेनले में पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है।

केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यटन, विकास और कल्याण का केंद्र बनने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेनी चाहिए।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

भ्रष्टाचार के प्रति केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और आईटी-सक्षम पहल की शुरूआत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय परिवर्तन को बढ़ाया है, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है। यह दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है, जो केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक समृद्धि के नए मानकों के रूप में स्थापित करता है।

एक मजबूत निगरानी तंत्र विभिन्न प्रमुख और विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से न केवल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है, बल्कि आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं। वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों का समग्र विकास, उनके जीवन स्तर में सुधार और सरकारी योजनाओं की संतृप्ति हासिल करना निरंतर प्रक्रियाएं हैं। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे और रसद, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, जलीय कृषि और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों की सामूहिक क्षमता का लाभ उठाकर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहक्रियात्मक रूप से काम करना और जमीनी स्तर पर विकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इन प्रयासों के माध्यम से, केंद्र शासित प्रदेश न केवल अपने स्वयं के विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सहक्रियात्मक रूप से काम करके और जमीनी स्तर पर विकास पर ध्यान केंद्रित करके, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत 2047 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

बुनियादी ढांचा और शासन सुधार

हाल के वर्षों में केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों में हवाई, सड़क तथा समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाने को भी प्राथमिकता दे रही है। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ₹710 करोड़ की लागत वाला एक नया टर्मिनल भवन, अब सालाना 50 लाख यात्रियों को संभालता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हम्फ्री स्ट्रेट पर आजाद हिंद फौज सेतु के निर्माण से सड़क कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। वहीं, लद्दाख में जोजी-ला सुरंग जैसी परियोजनाएं बुनियादी ढांचे को और अधिक बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि शासन सुधारों और अनुपालन बोझ को कम करके 'व्यवसाय करने में आसानी' को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए एकल-खिड़की निकासी प्रणाली और नीतियों का कार्यान्वयन केंद्र शासित प्रदेशों में व्यावसायिक गतिविधियों और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहा है। निवेश प्रोत्साहन योजनाएं पर्यटन, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी और ब्याज सब्सिडी प्रदान करती हैं। रोजगार पैदा करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि जैसे प्रमुख कार्यक्रम प्रभावशाली रूप से लागू किए गए हैं। ये प्रारंभिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं।

विकास की नई गाथा

ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना है। केंद्र सरकार का यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे क्षेत्र विशेष में विकास के अवसरों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। यह एक नए युग की शुरुआत का आरंभ है, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विशिष्टताओं को मान्यता और उनकी आवश्यकताओं को समझने में मदद करेगा। यह समाज को समृद्धि, स्वतंत्रता और विकास की दिशा में अधिक सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

अलग-अलग शासन संरचनाओं के आगमन के साथ ही उसके अनुरूप योजनाओं की शुरुआत की गई। इससे जनता को सीधे लाभ मिल रहा है।

> **हम 'विकसित जम्मू-कश्मीर' बनाएंगे और इसे हासिल करने के लिए केंद्र सरकार हाशिए पर रहने वाले लोगों, किसानों, युवाओं एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही है।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

कश्मीर घाटी, जम्मू क्षेत्र और लद्दाख के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।

स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में आश्वासन दिया था कि राज्य पुनर्गठन क्षेत्र के भविष्य और

बेहतर विकास के लिए तैयार है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश आखिरकार उचित समय पर अपनी विधान सभाओं की बहाली के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करेंगे। विकास के लिए आवश्यक संरचनात्मक बदलाव को समर्थन करेगा। इससे न केवल विकास होगा, बल्कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक उत्थान की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ेगी।

विकास को बढ़ावा देने और बाधाओं को अलग करने के लिए रणनीतियों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों को कमजोर करने का प्रयास और आतंकवाद के लिए वित्त पोषण स्रोतों की पहचान करना और उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चलाना विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल स्थानीय आर्थिक एवं सामाजिक संरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अलगाववादियों को लेकर जनता का विश्वास कम हो गया है। असल में, यह स्थानीय पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना के बीच आपसी सहयोग एवं बेहतर समन्वय का परिणाम है। आतंकवाद और अलगाववाद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नेटवर्क की भी पहचान कर ली गई है। आतंकवाद के लिए वित्त पोषण की रीढ़ तोड़ने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों को मजबूत किया गया है। आतंकी फंडिंग और नकली मुद्रा रैकेट की जांच के लिए नकली भारतीय मुद्रा नोट समन्वय समूह और टेरर फंडिंग, नकली मुद्रा सेल जैसे समन्वय समूह स्थापित किए गए हैं। बाड़ लगाने और गश्त बढ़ाने के साथ सीमा पर चौबीसों घंटे निगरानी बढ़ा दी गई है।

बीते एक दशक में जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब यहां के लोगों को मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिला है।

जम्मू-कश्मीर के स्थितिगत सुधार में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने एक लेख के जरिए जम्मू-कश्मीर पर अपने विचार देश के साथ साझा किए थे। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जिससे मोहभंग, निराशा की जगह विकास, लोकतंत्र और गरिमा में नया विश्वास आया है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को उनका हक नहीं मिलता था, और युवाओं की आकांक्षाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के महत्वपूर्ण निर्णय का जिक्र करते हुए कहा कि 5 अगस्त, 2019 ने सब कुछ बेहतरी के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, 'सभी केंद्रीय कानून अब बिना किसी डर या पूर्वाग्रह के क्षेत्र में लागू हैं।'

वीर नायकों के नाम पर हुआ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीपों में से इक्कीस द्वीपों का नाम देश के 21 'परमवीर चक्र' पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है। देश की ओर से अपने वीर नायकों को यह सम्मान है। यह पहल उनके वीरतापूर्ण योगदान को याद करती है और भारतीय इतिहास की समृद्ध परंपरा को पुष्ट करती है।

ब्यूरो

केंद्रीय गृह मंत्रालय का नेतृत्व संभालने के बाद से श्री अमित शाह देश के उपेक्षित नायकों को सम्मान देने पर काम कर रहे हैं। 15 अक्टूबर, 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने देश वीर नायकों के नाम पर द्वीपों का नाम रखने का संकल्प लिया था। उसके दो साल बाद, 23 जनवरी, 2023 को, जिसे 'पराक्रम दिवस' के रूप में भी अब जाना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 21 बड़े द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीरों तक, सभी का एक ही संकल्प था–राष्ट्र प्रथम! भारत प्रथम! यह संकल्प अब इन द्वीपों के नाम पर हमेशा के लिए अमर हो गया है।

इससे पहले, 2018 में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था। इसी प्रकार, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। इतना ही नहीं, अंडमान में एक पहाड़ी कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर भी समर्पित की गई, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 'ये दिल मांगे मोर' का नारा दिया था।

अंग्रेजों ने इन द्वीपों को अपने संस्कृतियों और इतिहास के आधार पर नामित किया था, जो अक्सर उनके साम्राज्य और शासन के प्रतीक थे। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे द्वीपों के नाम पर भी गुलामी के निशान हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि यही वह स्थान है जहां पहली बार तिरंगा फहराया गया था। 30 दिसंबर, 1943 को, नेताजी ने अंडमान की अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल में पहली बार तिरंगा फहराया और द्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त क्षेत्र घोषित किया था।

21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम बदला गया

1. मेजर सोमनाथ शर्मा
2. मानद कैप्टन करम सिंह
3. द्वितीय लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे
4. नायक जदुनाथ सिंह
5. कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह
6. कैप्टन जीएस सलारिया
7. लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा
8. सूबेदार जोगिंदर सिंह
9. मेजर शैतान सिंह
10. सीक्यूएमएच अब्दुल हामिद
11. लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुर्जोरजी तारापोर
12. लांस नायक अल्बर्ट एक्का
13. मेजर होशियार सिंह
14. द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल
15. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों
16. मेजर रामास्वामी परमेश्वरन
17. नायब सूबेदार बाना सिंह
18. कैप्टन विक्रम बत्रा
19. लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय
20. सूबेदार मेजर संजय कुमार
21. सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव

पारदर्शिता के साथ बेहतर

ब्यूरो

भारत के राजनीतिक मानचित्र पर दिल्ली का एक अद्वितीय स्थान है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी एक विशिष्ट संघीय स्थिति है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के तत्वों को मिश्रित करती है। यद्यपि निर्वाचित सरकार है, इसकी शक्तियां केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के बीच विभाजित हैं।

केंद्र सरकार की मंशा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बेहतर विकास की रही है। दुनिया के तमाम देशों के लिए लोग यहां आते हैं। जो लोग पूरा भारत नहीं घूमते, वो दिल्ली की छवि से पूरे देश को देखते हैं। ऐसे में भारत सरकार दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने के लिए काम करती रही है। स्थानीय निकाय के रूप में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस परिषद के अंतर्गत ही दिल्ली के प्रमुख जगह आते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से कई काम होते हैं। उसकी निगरानी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है।

दिल्ली में जनता को बेहतर व्यवस्था मिले, इसके लिए अगस्त, 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया था जिसे सदन ने पास कर दिया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि दिल्ली का मामला अन्य राज्यों से अलग है। उन्होंने पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी तर्क दिया।

संसद में इस विधेयक को लेकर कई प्रकार की बातें हुईं। कई विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। जवाब देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि इस बिल का उद्देश्य है कि दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। बिल के प्रावधान में पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिल लाया गया है। इस बिल का मकसद है भ्रष्टाचार को रोकना। इसके उद्देश्य संविधान के मुताबिक ही है। इस बिल का कोई भी प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करते। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये विधेयक संपूर्णतया संविधानसम्मत है और सिर्फ दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए लाया गया है और इसके पीछे केंद्र सरकार का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 पर जवाब देते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। केंद्र को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों ने हमें शक्ति और अधिकार दिया है।

नई दिल्ली क्षेत्र को बेहतर बनाए रखने में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्ती भूमिका रहती

> **श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने हर क्षेत्र के विकास की पहल की और शहरी विकास के लिए एक व्यापक, परिणामोन्मुख और एकीकृत नीति बनाई है।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने समय-समय पर इनकी सुध ली है। 3 मई, 2023 को उन्होंने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के 4400 कर्मियों के नियमितीकरण पर नियुक्ति पत्र वितरित किए। इससे लोगों में नया उत्साह दिखा। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने फैसले लेने की अपनी क्षमता के कारण कई क्षेत्रों में अनिश्चितताओं का अंत करने में सफलता प्राप्त की है और उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आज का ये कार्यक्रम है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं भारत सरकार के हर मंत्रालय में नौकरी की शर्तों और भर्ती के नियमों में समयानुकूल बदलावों पर बहुत जोर दिया है और उसी का नतीजा है कि

व्यवस्था

आज एक मायने में सिर्फ 4400 कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में कई कर्मचारियों के लिए भी सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। श्री शाह ने कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां देश की नीतियों का निर्धारण होता है, विदेशी मेहमान आते हैं और पूरे विश्व में भारत के संदेश और सुगंध को फैलाने के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की ज़िम्मेदारी है।

सरकारी कर्मचारियों को रहने आदि की व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पुष्प विहार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 120 नए फ्लैट्स का भी लोकार्पण हो रहा है। रंजीत सिंह फ्लाईओवर और सफदरजंग फ्लाईओवर का अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कई क्षेत्रों में विकास की नींव डालने वाले व्यक्ति हैं। 2014 के बाद मोदी ने हर क्षेत्र में विकास करने के लिए आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी उठाई और विस्तृत, परिणामलक्षी और एकीकृत अर्बन डेवलपमेंट की नीति बनाई, जो 5 स्तंभों पर आधारित है, जिसके तहत शहर के गवर्नेंस को सुधारने का बीड़ा उठाया, ई-गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी मिशन, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से शहर के शासन को सुधारने का काम किया। इसके साथ ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कई योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार ने कई बदलाव किए, जैसे अमृत मिशन, रेरा कानून, मेट्रो के जाल और इलेक्ट्रिक बसों से शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर और वातावरण में बदलाव देखने को मिला है।

नई दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से समय-समय पर तमाम चीजों की समीक्षा की जाती है। कई मंचों पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आजादी से लेकर आज तक अपने गौरवशाली इतिहास से दिल्ली पुलिस ने पूरे देश की प्रशंसा हासिल की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई देशों के दूतावास और बड़े-बड़े लोगों के आवास हैं और पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ करती है। दिल्ली

> **संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने के लिए पूरा अधिकार है।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

पुलिस 'शांति, सेवा, न्याय' के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ी और लक्ष्य में बदलाव के साथ 75 वर्षों की इस यात्रा में दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों, गतिविधियों और विचारों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश और दुनिया कोविड-19 महामारी से गुजरी थी, उस समय दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा सबके सामने आया, जिसने देश और दुनिया में इसकी छवि बदल दी।

दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आम नागरिकों के साथ-साथ दूतावास और अति महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की सराहना की। उन्होंने आजादी से लेकर वर्तमान तक के दिल्ली पुलिस के सराहनीय इतिहास के लिए प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल करके अनुकरणीय आचरण और मानवता का परिचय दिया। पूरी महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 'शांति, सेवा, न्याय' के अपने आदर्श वाक्य को दृढ़ता से बरकरार रखा है। ■

दशकों पुरानी आकांक्षा हुई पूरी

ब्यूरो

अनेकता में एकता के बीच अपना एक अलग रंग बिखरने वाला लद्दाख, देश की राजधानी नई दिल्ली से भौगोलिक रूप से दूर होने के कारण मानो विकास की रोशनी से छूट-सा गया था। यहां के लोगों के मन में एक टीस -सी महसूस हो रही थी। लेकिन, बीते दशक में जिस प्रकार से लद्दाख पर भारत सरकार की खास नजर पड़ी है उसके बाद से यहां के लोगों की दशकों पुरानी इंच्छाए अब मूर्त रूप लेने लगी हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस क्षेत्र के लिए कई विशेष काम किए हैं। हाल के वर्षों में जैसे ही लद्दाख, जम्मू-कश्मीर से अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके बाद यहां विकास की गति तेज हो गई है। केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से अब लद्दाख स्वतंत्रता पूर्वक अपने विकास का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रहा है।

> **संविधान के अनुच्छेद 370 का समाप्त होना लद्दाख क्षेत्र के लिए नया सवेरा है। केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों को देश के शेष हिस्सों के साथ लाने के लिए वचनबद्ध है।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

लद्दाख के विकास में तेजी ला रही है केंद्र सरकार

केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय लद्दाख के विकास कार्य को तेजी से करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता 4 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित लद्दाख के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में साफ तौर पर दिखी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल), कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) और कारगिल से भागीदारी देखी गई। श्री राय ने 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद से हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि इस ऐतिहासिक कदम ने शासन और विकास को लोगों के करीब ला दिया है। प्रमुख पहलों में बजटीय आवंटन में वृद्धि, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के लिए बढ़ी हुई फंडिंग, बेहतर कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क, सड़कों और नए हेलीपैड जैसी त्वरित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। बैठक में एबीएल और केडीए द्वारा प्रस्तुत मुद्दों को भी संबोधित किया गया, जिसमें निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा, फास्ट-ट्रैक भर्ती प्रक्रियाएं और निर्णय लेने में अधिक भागीदारी शामिल है। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के समग्र और सतत विकास के लिए स्थानीय निकायों के साथ नियमित रूप से जुड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

गृह मंत्री श्री अमित शाह का कहना है कि सरकार लद्दाख के विकास और उसकी भूमि व संस्कृति के संरक्षण के प्रति संकल्पित है और सरकार ने लद्दाख के लोगों की दशकों से लंबित संघ शासित राज्य की मांग को पूर्ण कर अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

लद्दाख में समेकित विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के समग्र विकास के लिए 63 परियोजनाओं के साथ प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 की घोषणा की, जिसकी कुल लागत ₹80,068 करोड़ थी।

इन 63 परियोजनाओं में से ₹21,441 करोड़ की 9 परियोजनाएं विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए है। इतना ही नहीं, लद्दाख के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करके इसे 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में प्रति वर्ष ₹5958 करोड़ किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार लद्दाख के विकास के लिए समीक्षा करता रहता है। केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में लद्दाख अहम है। केंद्र सरकार लगातार कई योजनाओं को यहां लागू कर रही है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कई बार इस प्रतिबद्धता को दोहरा चुके हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने कई संबोधनों में इस बात का उल्लेख किया है कि लद्दाख के लोगों का विकास, भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल की डेवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार, विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचा रही है। लद्दाख में स्पीरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है।

सोलर पावर जनरेशन का भी लद्दाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। अब वहां के सामर्थ्य का उचित इस्तेमाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे। अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा। ■

चंडीगढ़ में बहती रहेगी विकास की बयार

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में चंडीगढ़ में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं और सुधार किए गए हैं। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है, जिसके अंतर्गत शहर में बुनियादी ढांचे का सुधार, यातायात प्रबंधन और स्मार्ट तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। चंडीगढ़ में सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जिससे नागरिकों को आसानी से सेवाएं मिल सकें। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।

22 दिसंबर, 2023 को जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह चंडीगढ़ प्रवास पर थे, तब उन्होंने वहां कई योजनाओं की शुरूआत की। पहले से चल रही कई व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आगे के लिए निर्देश दिए। सेक्टर 26 स्थित चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी (सीसीईटी) के प्रांगण में श्री अमित शाह ने चंडीगढ़ पुलिस में शामिल 44 नए एसआई और 700 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। गृहमंत्री ने पुलिस विभाग में नए सब इंस्पेक्टरों और कांस्टेबल की नियुक्ति पत्र के साथ ही पुलिस विभाग को 25 टाटा सफारी वाहन भी सौंपे। चंडीगढ़ पुलिस ने ₹3 .75 करोड़ से इन वाहनों की खरीद की है। शहर में प्रदर्शन, उपद्रव आदि घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए करीब ₹75 लाख की लागत से खरीदे गए बुलेट प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल कवच को भी उन्होंने पुलिस को सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन चंडीगढ़ के लिए खुशी का दिन है। विकास की यह बयार यूं ही बहती रहेगी।

चंडीगढ़ की सुरक्षा के लिए कुछ वाहनों की भी शुरूआत हुई है और 744 युवाओं को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के रूप में नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने बीट के कॉन्सेप्ट को पुनर्जीवित करने की बात को बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि आज देश के कई राज्यों की पुलिस ने कमोबेश इसी पैटर्न पर चलते हुए इस व्यवस्था को स्वीकारा है।

> **दिसम्बर 2024 तक सभी केन्द्रशासित प्रदेशों में इन तीनों कानूनों पर अमल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, मानव संसाधन की ट्रेनिंग और कोर्ट के पूर्ण कम्प्यूटराइज़ेशन का काम हो जायेगा।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

पुलिस के सामने अलग प्रकार की चुनौतियों, विशेषकर टेक्नोलॉजी से संबंधित के समाधान के लिए हैकाथॉन के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की बात कही गई थी। इसके माध्यम से देशभर के युवाओं को अपने ज्ञान का उपयोग देश की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि यहां साइबर ऑपरेशन और सुरक्षा केन्द्र (CenCOPS) का भी उद्घाटन हुआ है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि दिसंबर, 2024 तक सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में इन तीनों कानूनों पर अमल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर,

संसद द्वारा तीनों विधेयकों के पारित होने के अगले दिन ही गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में साइबर ऑपरेशन और सुरक्षा केंद्र (CenCOPS) में इन कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

सॉफ्टवेयर, मानव संसाधन की ट्रेनिंग और कोर्ट के पूर्ण कंप्यूटराइजेशन का काम हो जाएगा। आतंकवाद, संगठित अपराध की व्याख्या पर अमल, डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन के गठन, फॉरेंसिक को स्थायित्व देने और आईसीजेएस और सीसीटीएनएस में लूपहोल्स खत्म करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनेगा।

इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारीलाल पुरोहित और केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने कहा कि यहां ₹368 करोड़ की लागत वाली 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और 32 करोड़ रूपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ आधुनिक कल्पना के साथ बसाया गया एक पूर्ण शहर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से कई शहर आगे बढ़ रहे हैं और चंडीगढ़ को इस स्पर्धा में रहते हुए अपने आप को साबित करना होगा और पहला स्थान बनाए रखने के लिए बहुत काम करना होगा।

चंडीगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और हरे-भरे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अभियानों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी और निजी भवनों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए नए अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का भी आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि यहां लगभग ₹400 करोड़ की लागत से स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षा, आवासीय सुविधाएं और उच्च शिक्षा के कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं।

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अब क्षेत्रीय भाषाओं में सीएपीएफ की होगी परीक्षा

ब्यूरो

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय स्थानीय भाषाओं और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, स्थानीय युवाओं को समाज में अधिक समाहित और भागीदार बनाने का भी एक प्रयास है। इस निर्णय से,स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को महत्व दिया जा रहा है और लोगों को अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व महसूस होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक समावेशन और विकास को बढ़ावा देगा और देश की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करेगा। इस प्रकार, यह निर्णय राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समावेशन को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी सोच को अमलीजामा पहनाया है प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने। सरकार ने पहली जनवरी, 2024 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने का फैसला किया था। कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया गया। इसमें शामिल हैं-असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी। इस ऐतिहासिक निर्णय से देशभर के लाखों युवा अपनी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे जिससे उनके चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में परीक्षार्थियों के बीच इस परीक्षा की पहुंच बढ़ेगी और सभी को रोजगार का समान अवसर भी मिलेगा। कांस्टेबल (जीडी) चयन परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है जो देश भर से लाखों युवाओं को आकर्षित करती है।

गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा, 2024 को अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है।

दरअसल, देश भर से लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं और कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की संख्या अन्य परीक्षाओं से ज्यादा होती है। केंद्र सरकार की इस पहल से

जब परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं में होंगी, तो युवा अधिक प्रोत्साहित होंगे। जिसका परिणाम सकरात्मक होगा। पहला युवाओं का बेहतर भविष्य और दूसरा देश में फैलता है विकास का परचम। साथ ही इस प्रोत्साहन से उनमें भाषा को लेकर मानसपटल में झिझक नहीं रहेगी कि अंग्रेजी या हिंदी का ज्ञान अधूरा है।

देशभर के युवाओं को अपनी मातृभाषा में सीएपीएफ कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा में भाग लेने और राष्ट्र की सेवा में अपना करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिला है।

सीमा पर स्थित गांव है देश का प्रथम गांव

जब तक देश का प्रथम गांव विकसित नहीं होता, तब तक एक विकसित भारत नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के माध्यम से दिलों की दूरी कम करने का काम किया है। चरणबद्ध तरीके से गांव का विकास, पलायन रोकना व संस्कृति का संरक्षण, कनेक्टिविटी, मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

ब्यूरो

दिलों की दूरियां पाटने से ही कम होती हैं। ऐसी दूरी भारत के सीमावर्ती गांवों और दिल्ली के बीच थी। इन दूरियों को कम करने का काम प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के माध्यम से किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक देश का प्रथम गांव विकसित नहीं होता, तब तक एक विकसित भारत नहीं बन सकता। उनका मानना है कि सीमा पर स्थित गांव देश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गांव है। साथ ही पहले इन सीमावर्ती गांवों में मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण यहां से पलायन होता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्थानीय लोगों के लिए सुविधाओं की चिंता कर वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के माध्यम से पलायन की समस्या को दूर करने के प्रयास किए हैं। ऐसी बातें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 25 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के गांवों के विशेष अतिथियों के साथ संवाद में कहीं। इस अवसर पर पृथ्वीविज्ञान मंत्री, श्री किरेन रिजिजू, सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और गृह राज्यमंत्री तथा युवा कार्यक्रम व खेल राज्य मंत्री, श्री निशिथ प्रमाणिक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

वाइब्रेंट विलेजेज के पंच और सरपंच अपने परिवारों के साथ भारत सरकार के 'विशेष अतिथि' के रूप में कर्तव्य पथ पर इस साल की गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनें थे। वाइब्रेंट विलेजेज से आए विशेष अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा भी किया। इन सभी ने 27 जनवरी को 'भारत पर्व' में भाग लिया। इसके साथ ही विशेष अतिथियों को 27 जनवरी को होने वाली एनसीसी कैडेटों की 'पीएम रैली' देखने के लिए भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में 19 सीमावर्ती क्षेत्रों के 3 हजार गांवों को कवर किया जा रहा है और ये कार्यक्रम 10 सालों में पूरा हो जाएगा। इस योजना के पहले चरण में 662 गांवों को कवर किया जा रहा है, जिनकी कुल आबादी 1,42,000 है और सरकार इस पर ₹4800 करोड़ खर्च कर रही है।

भौगोलिक रूप से देश के सीमावर्ती गांवों और राजधानी दिल्ली के बीच दूरी भले अधिक हो, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के जरिए लोगों के दिलों को करीब ला दिया है। जब तक देश का पहला गांव विकसित नहीं होगा, विकसित भारत नहीं बन सकता है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के 3 उद्देश्य हैं– चरणबद्ध तरीके से देश के प्रथम गांव का संपूर्ण विकास, सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकना और स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करना और गांवों में हर प्रकार की कनेक्टिविटी में सुधार, मूलभूत सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। इन क्षेत्रों में ₹2500 करोड़ के खर्च से सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों को सुविधा होगी।■

विकास के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में रणनीतिक पहल

दिनकर गुप्ता

भारत के विशाल प्रशासनिक संरचना में केंद्र शासित प्रदेशों ने अक्सर पाया है कि उनकी अनूठी चुनौतियों को बड़े राज्यों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। हालांकि, वर्ष 2014 के बाद से, एक परिवर्तनकारी बदलाव चल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर सोच बदली है। ये प्रदेश नवाचार के साथ-साथ प्रगति के लिए उपजाऊ आधार के रूप में उभरे हैं।

भारतीय संघ में 28 राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के पास पूर्ण सरकारी संरचना है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में शासन को लेकर कुछ सीमाएं हैं।

इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की संरचना में कुछ भिन्नताएं और सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल है, लेकिन उसके पास पुलिसिंग शक्तियां नहीं हैं। जबकि पुडुचेरी में एक निर्वाचित सरकार भी है जिसके पास पुलिसिंग शक्तियां भी हैं। इसके विपरीत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित सरकारें नहीं हैं।

आकार और संरचना में भिन्नताओं के कारण साल 2014 से पहले कई केंद्र शासित प्रदेशों पर ध्यान नहीं दिया गया था। अब, उन्हें अपने विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के लिए संसाधन और महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्राप्त हो रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रणी पायलट परियोजनाओं के लिए लॉन्च पैड के रूप में उपयोग किया है। इससे राज्यों में उनके व्यापक कार्यान्वयन से पहले नई योजनाओं और पहलों के परिणामों का मूल्यांकन करना संभव हो गया है।

केंद्र सरकार ने अधिक प्रभावी शासन के लिए केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। वहीं, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक इकाई में मिला दिया गया था।

केंद्र शासित प्रदेशों में कई उल्लेखनीय आर्थिक सफलताएं और मानव विकास के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने स्वायत्तता और विकास के क्षेत्र में ठोस प्रयास किए हैं, जिससे इन प्रदेशों में जीवन स्तर में सुधार आया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन, स्वायत्तता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है। पूर्ण विद्युतीकरण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज और 100% इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से पारदर्शी वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित करने जैसी राष्ट्रीय पहल केंद्र शासित प्रदेशों में सफल रही हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक विकास और मानव विकास में सुधार आया है, जो राज्यों से आगे निकलने में मदद कर रहा है।

'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत के प्रसार से, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक सुधार हुए हैं। इसे अपनाकर, प्रत्येक प्रदेश अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उसकी विकास की गति को बढ़ावा मिले। उदाहरण के रूप में, दमन और दीव और चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण ने सेवा की गुणवत्ता और परिचालन दक्षता में सुधार किया है।

केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। हाल ही में, सिलवासा में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जबकि चंडीगढ़ ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में ग्रेड 1++ हासिल किया था। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, चंडीगढ़ ने शहर-व्यापी सार्वजनिक बाइक-शेयरिंग (पीबीएस) नेटवर्क के साथ 200 किलोमीटर से अधिक बाइक लेन और पैदल मार्ग विकसित किए, जिसमें 617 स्टेशनों पर 5,000 साइकिलें शामिल थीं। इन पहलों ने प्रदेश के स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और नए हवाई अड्डे के विकास के द्वारा कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी केबल परियोजना जैसी परियोजनाओं के साथ बुनियादी ढांचे में वृद्धि जारी है। इसी तरह, सागरमाला योजना द्वारा वित्त पोषित पुडुचेरी बंदरगाह विकास परियोजना भी एक महत्वपूर्ण पहल है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से, पुडुचेरी के युवाओं को अब अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ मिलता है।

चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक विकास ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनभागीदारी मॉडल के तहत समुदाय-संचालित पहल के साथ, पर्यटन स्थलों को नया रूप मिल रहा है। पिछले एक दशक में, केंद्र शासित प्रदेशों में 'स्वदेश दर्शन' और 'PRASHAD' (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान) योजनाओं के तहत ₹1,400 करोड़ से अधिक मूल्य की 52 पर्यटन-संबंधित परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

इस प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश सटीक शासन और समुदाय-संचालित पहल के माध्यम से विकास के सफल उदाहरण साबित हुए हैं। वे वस्तुनिष्ठ योजना के माध्यम से विकास के मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। रणनीतिक प्रयासों के साथ, जैसा कि हमने हाल ही में लक्षद्वीप में देखा था, स्वयं प्रधान मंत्री की यात्रा के साथ, केंद्र शासित प्रदेश विकास और प्रगति के एक नए युग की शुरूआत कर रहे हैं।■

(पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी)

18 जनवरी को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने शिलॉन्ग स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्युरिटी ऑपरेशंस सेंटर का उद्घाटन किया। साइबर सिक्युरिटी ऑपरेशंस सेंटर असम राइफल्स वाइड एरिया नेटवर्क में नेटवर्क की वास्तविक समय के आधार पर निगरानी) बाहरी खतरों को कम करने और साइबर उल्लंघनों की रोकथाम कर साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगा।

गृह मंत्रालय ने आरडी-2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी-पीपुल्स चॉइस ट्रॉफी के लिए वोट जीता। आईटीबीपी को झांकी में वाइब्रेंट विलेज थीम को प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह झांकी कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों ने केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला को ट्रॉफी सौंपी।

नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) ने 19 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के 38 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपने 8वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर, एनसीजीजी के महानिदेशक, श्री वी श्रीनिवास ने सुशासन के लिए जम्मू-कश्मीर द्वारा अपनाई जा रही डिजिटल प्रथाओं की प्रशंसा की। दो सप्ताह का यह कार्यक्रम नागरिक-केंद्रित शासन में नवीन प्रथाओं के लिए सूचना और ज्ञान साझा करने पर केंद्रित था।

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT
PLEASE SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE CHANNEL
POLICE AUR SEVA

आप ऑनलाइन सुरक्षित रहें, इसकी बानगी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के यूट्यूब चैनल 'पुलिस और सेवा' एक वीडियो में दिखती है। इस वीडियो में ऑनलाइन सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है, जिसके प्रमुख बिंदु हैं- केवल विश्वसनीय वेबसाइट्स और एप्पेस का ही उपयोग करें, अपनी निजी जानकारी को गोपनीय रखें, हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाएं और एक से अधिक खातों के लिए अलग-अलग पासवर्ड बनाएं तथा अज्ञात स्त्रोतों से लिंक पर क्लिक करने या डाउनलोड करने से बचें। यदि आप साइबर क्राइम के शिकार बन गए हैं, तो 1930 पर कॉल करें और www.cybercrime.gov.in पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करें।

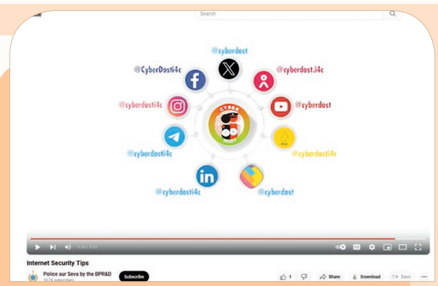

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

केंद्र शासित प्रदेश भौगोलिक आकार में छोटे हैं और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अपेक्षाकृत सरल है, इसलिए वे पायलट कार्यक्रमों के साथ प्रयोग करने के लिए आदर्श प्रोटोटाइप हैं। इन प्रयोगों का परीक्षण केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे पैमाने पर किया जा सकता है और फिर बड़े क्षेत्रों और राज्यों में दोहराया जा सकता है।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037